Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
Special Issue on Integrating Science, Arts, Commerce and Technology for Future Innovations 7(12s)

IMPROVING RURAL LIVELIHOODS IN BIHAR THROUGH MGNREGA: CHALLENGES AND PROSPECTS

बिहार में मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण जीवन में सुधार: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

Juhi Kumari [1], Dr. Kishore Parth [2]

[1] Research Scholar, Department of commerce Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur, India
[2] Assistant Professor, Department of Management, L.N. Mishra College of Business Management, India

Received 12 March 2026
Accepted 14 May 2026
Published 26 May 2026

Corresponding Author
Juhi Kumari, Juhi.Kumari@outlook.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v7.i12s.2026.8362

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) is a flagship rural employment scheme of the Government of India, aimed at providing a minimum of 100 days of wage-based employment to rural households. In an economically backward state like Bihar, this scheme has made a significant contribution towards improving rural living standards. The objective of the present study is to analyze the impact, challenges, and future prospects of MGNREGA in the rural areas of Bihar. The study utilizes both primary and secondary data. Primary data were collected through questionnaires and interviews, while secondary data were drawn from government reports, economic surveys, and published research papers. Various studies have found that MGNREGA has played a pivotal role in reducing rural unemployment, enhancing income levels, encouraging women's participation, and building rural infrastructure. Recent evaluation studies in Bihar have also revealed that the scheme has had a positive impact on livelihood security; however, issues such as delayed wage payments, administrative irregularities, and a lack of awareness persist. The study concludes that if transparency, social audits, and digital management mechanisms are strengthened, MGNREGA has the potential to further bolster the living standards of rural communities in Bihar.

Hindi: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करना है। बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इस योजना ने ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के प्रभाव, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करना है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े प्रश्नावली एवं साक्षात्कार द्वारा एकत्र किए गए, जबकि द्वितीयक आँकड़े सरकारी रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण तथा प्रकाशित शोधपत्रों से लिए गए। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि मनरेगा ने ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने, आय बढ़ाने, महिला सहभागिता को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार में हाल के मूल्यांकन अध्ययनों में भी यह सामने आया है कि योजना ने आजीविका सुरक्षा में सकारात्मक प्रभाव डाला, हालांकि भुगतान में देरी, प्रशासनिक अनियमितता और जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यदि पारदर्शिता, सामाजिक लेखा परीक्षा तथा डिजिटल प्रबंधन को मजबूत किया जाए तो मनरेगा बिहार के ग्रामीण जीवन स्तर को और अधिक सुदृढ़ बना सकता है।

Keywords: MNREGA, Rural Development, Bihar, Employment, Poverty Alleviation, Social Security, Women Empowerment, मनरेगा, ग्रामीण विकास, बिहार, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण

How to cite this article (APA): Kumari, J., and Parth, K. (2026). Improving Rural Livelihoods in Bihar Through MGNREGA: Challenges and Prospects. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 7*(12s), 137–149. doi: 10.29121/shodhkosh.v7.i12s.2026.8362

1. प्रस्तावना

भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, अल्प आय, मौसमी पलायन तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी लंबे समय से प्रमुख समस्याएँ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) लागू किया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का अकुशल श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि जल संरक्षण, सड़क निर्माण, तालाब निर्माण और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन भी है। बिहार में, जहाँ बड़ी आबादी कृषि और असंगठित श्रम पर निर्भर है, मनरेगा ग्रामीण जीवन में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है।

साहित्यसमीक्षा शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें किसी विषय से संबंधित पहले से किए गए अध्ययनों, शोध पत्रों, पुस्तकों और अन्य स्रोतों का व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि उस विषय पर अब तक क्या-क्या कार्य हो चुका है, किन-किन निष्कर्षों पर शोधकर्ता पहुँचे हैं, और अभी किन क्षेत्रों में और शोध की आवश्यकता है। साहित्य समीक्षा केवल जानकारी एकत्र करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह विभिन्न शोधों की तुलना, उनके तरीकों, निष्कर्षों और सीमाओं का आलोचनात्मक अध्ययन भी करती है। इससे शोधकर्ता को अपने अध्ययन के लिए एक मजबूत आधार (theoretical base) मिलता है और वह अपने शोध की दिशा स्पष्ट कर पाता है।साहित्य समीक्षा के माध्यम से शोधकर्ता यह पहचानता है कि उसके शोध का नवीनता (novelty) क्या है और वह पहले के अध्ययनों से कैसे भिन्न है। यह शोध में दोहराव (duplication) से बचने में मदद करती है तथा शोध समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में सहायक होती है।अच्छी साहित्य समीक्षा में स्रोतों का चयन विश्वसनीय और प्रासंगिक होना चाहिए, जैसे कि जर्नल आर्टिकल, शोध प्रबंध, सरकारी रिपोर्ट आदि। इसमें तथ्यों को क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि पाठक को विषय की स्पष्ट समझ मिल सके।संक्षेप में, साहित्य समीक्षा किसी भी शोध का आधार स्तंभ होती है, जो शोधकर्ता को सही दिशा प्रदान करती है, उसके अध्ययन को प्रमाणिक बनाती है और शोध के ज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Biswas (2015) ने अपने शोध में रोजगार सृजन और परिसंपत्ति निर्माण का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में भी द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते हुए पाया गया कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी प्रगति में कमी तथा वंचित वर्गों की सीमित भागीदारी देखी गई।दोनों अध्ययनों में सुझाव दिया गया है कि मनरेगा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, समय पर भुगतान, महिलाओं के लिए बेहतर कार्यस्थल सुविधाएँ तथा सामाजिक समावेशन को मजबूत किया जाना चाहिए।

Nagaraj et al. (2016) ने अपने शोध में कृषि मजदूरी, उत्पादकता एवं लागत पर प्रभाव का अध्ययन किया।इस अध्ययन में प्राथमिक फील्ड डेटा का उपयोग करते हुए सांख्यिकीय उपकरण जैसे ट्रेंड एनालिसिस (Trend Analysis), तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) एवं प्रतिशत विश्लेषण अपनाए गए, जिससे यह पाया गया कि मनरेगा के बाद कृषि एवं गैर-कृषि मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा श्रम का कृषि से गैर-कृषि क्षेत्र की ओर स्थानांतरण हुआ, हालांकि लैंगिक वेतन असमानता बनी रही।दोनों अध्ययनों में सुझाव दिया गया है कि मनरेगा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण, तकनीकी उन्नयन, श्रमिकों के कौशल विकास (विशेषकर महिलाओं के लिए) तथा श्रम बाजार में समानता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

Das (2016) ने अपने शोध से अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य असम के बरपेटा जिले में मनरेगा के प्रभाव और रोजगार सृजन की भूमिका का मूल्यांकन करना था।इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का उपयोग करते हुए वर्णनात्मक शोध पद्धति (Descriptive Method) अपनाई गई।सांख्यिकीय उपकरणों में प्रतिशत विश्लेषण (Percentage Analysis), तालिका विश्लेषण (Tabular Analysis) तथा तुलनात्मक अध्ययन का उपयोग किया गया, जिससे यह पाया गया कि मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों को रोजगार सुरक्षा प्रदान की, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दिया।अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि योजना के बेहतरक्रियान्वयन, जागरूकता बढ़ाने, समय पर मजदूरी भुगतान और स्थानीय स्तर पर निगरानी को मजबूत करने से मनरेगा के प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

Chahal एवं Kumar (2020) नेअपने शोध अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य हरियाणा राज्य में मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन के प्रभाव का विश्लेषण करना था।इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा का उपयोग करते हुए प्रतिशत विश्लेषण (Percentage Analysis), तालिका विश्लेषण (Tabular Analysis) एवं वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन किया गया, जिससे यह पाया गया कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन में सुधार तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने से मनरेगा की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

Pandey (2023) ने अपने लेख मे अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में 2011–12 से 2020–21 की अवधि के दौरान मनरेगा के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था।इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा (Secondary Data) जैसे सरकारी रिपोर्ट एवं आधिकारिक आँकड़ों का उपयोग किया गया।पद्धति के रूप में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति (Descriptive and Analytical Method) अपनाई गई।सांख्यिकीय उपकरणों में प्रतिशत विश्लेषण (Percentage Analysis), प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis) तथा तालिका विश्लेषण (Tabular Analysis) का उपयोग किया गया।अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि मनरेगा ने छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन, आय सुरक्षा एवं ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई।हालांकि, कुछ क्षेत्रों में कार्यान्वयन की धीमी गति, संसाधनों का असमान वितरण तथा निगरानी की कमी जैसी समस्याएँ भी पाई गईं।अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण, पारदर्शिता, समय पर भुगतान तथा प्रभावी निगरानी तंत्र के माध्यम से मनरेगा की कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

Shah (2024) नेअपने शोध में अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में मनरेगा कार्यों को अपनाने को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना था।इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा (Secondary Data) एवं राज्य-स्तरीय आँकड़ों का उपयोग किया गया।पद्धति के रूप में अनुभवजन्य (Empirical) एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति (Analytical Method) अपनाई गई।सांख्यिकीय उपकरणों में प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis), सहसंबंध विश्लेषण (Correlation Analysis) तथा तुलनात्मक अध्ययन का उपयोग किया गया।अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि मनरेगा के कार्यों को अपनाने पर सामाजिक-आर्थिक कारक, रोजगार की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे का विकास तथा सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।यह भी पाया गया कि योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए, सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित किया तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास में योगदान दिया।अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि जागरूकता बढ़ाने, प्रशासनिक दक्षता सुधारने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा कमजोर वर्गों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से मनरेगा की प्रभावशीलता और बढ़ाई जा सकती है।

Raju एवं Sharma (2025) ने अपने लेख में अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में 2014–2023 के दौरान मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन और हाशिए पर स्थित वर्गों की भागीदारी का विश्लेषण करना था। इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा का उपयोग करते हुए प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis), प्रतिशत विश्लेषण एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय उपकरण अपनाए गए, जिससे यह पाया गया कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, विशेषकर महिलाओं, SC और ST वर्गों की भागीदारी में सुधार हुआ, हालांकि 100 दिनों के रोजगार को पूरा करने वाले परिवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।दोनों अध्ययनों में सुझाव दिया गया है कि योजना के बेहतर उपयोग के लिए जागरूकता बढ़ाने, कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने, रोजगार के दिनों की उपलब्धता बढ़ाने तथा हाशिए पर स्थित वर्गों की भागीदारी को और सशक्त करने की आवश्यकता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य (OBJECTIVES)

1) बिहार में मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना।
2) ग्रामीण जीवन स्तर में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।
3) योजना के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
4) योजना की भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करना।
5) ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन करना।

3. परिकल्पनाएँ (HYPOTHESES)

H_0 (शून्य परिकल्पना):

मनरेगा का बिहार के ग्रामीण जीवन स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना):

मनरेगा का बिहार के ग्रामीण जीवन स्तर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

H_0: मनरेगा से ग्रामीण रोजगार के अवसरों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

H_1: मनरेगा से ग्रामीण रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

H_0: मनरेगा का ग्रामीण परिवारों की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

H_1: मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि की है।

H_0: मनरेगा का ग्रामीण पलायन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

H_1: मनरेगा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन में कमी आई है।

H_0: मनरेगा से महिलाओं की भागीदारी में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

H_1: मनरेगा से महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है।

H_0: प्रशासनिक एवं तकनीकी समस्याएँ मनरेगा के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करती हैं।

H_1: प्रशासनिक एवं तकनीकी समस्याएँ मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

4. कार्यप्रणाली (RESEARCH METHODOLOGY)

1) शोध की प्रकृति (Nature of Research)

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का है। इसमें मनरेगा के प्रभाव, उसकी कार्यप्रणाली, तथा ग्रामीण जीवन स्तर पर पड़े सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का गहन विश्लेषण किया गया है।

2) अध्ययन क्षेत्र (Study Area)

यह शोध बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, विशेष रूप से मुजफ्फरपुर जिला को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण एवं श्रमिक वर्ग से संबंधित है, इसलिए मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन यहाँ अधिक उपयुक्त है।

3) शोध डिज़ाइन (Research Design)

डिज़ाइन का प्रकार: Cross-sectional Study

दृष्टिकोण: Quantitative + Qualitative (मिश्रित पद्धति)

उद्देश्य: रोजगार सृजन का मूल्यांकन

आय स्तर एवं जीवन स्तर में परिवर्तन का अध्ययन

चुनौतियों एवं संभावनाओं का विश्लेषण

4) डेटा के स्रोत (Sources of Data)

- प्राथमिक डेटा (Primary Data):

संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire)

साक्षात्कार (Interviews) – लाभार्थियों, पंचायत प्रतिनिधियों, रोजगार सेवकों से फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD)

- द्वितीयक डेटा (Secondary Data):

ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट,बिहार आर्थिक सर्वेक्षण,जनगणना (Census) डेटा,शोध पत्र, जर्नल, एवं सरकारी प्रकाशन

5) नमूना चयन (Sampling Design)

Sampling Technique: Random Sampling (यादृच्छिक नमूना चयन)

Sample Size: 100 ग्रामीण परिवार

Sampling Unit: मनरेगा लाभार्थी परिवार

6) डेटा संग्रहण की विधि (Data Collection Methods)

प्रश्नावली विधि: आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित प्रश्न

साक्षात्कार विधि: गहराई से जानकारी प्राप्त करने हेतु

अवलोकन विधि (Observation): कार्यस्थल एवं ग्रामीण जीवन की वास्तविक स्थिति का अध्ययन

7) सांख्यिकीय उपकरण (Statistical Tools Used)

प्रतिशत विश्लेषण (Percentage Analysis)

तालिका एवं ग्राफ (Tables & Charts)

5. डेटा विश्लेषण (DATA ANALYSIS)

1) Data Structure

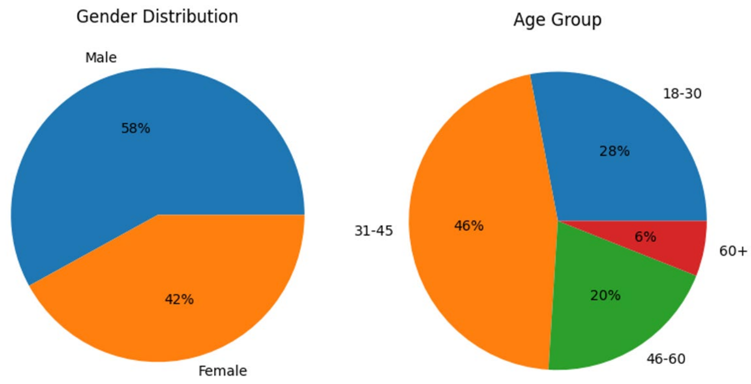

तालिका 1

तालिका 1 जनसांख्यिकीय प्रोफाइल		
श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
पुरुष	58	58%
महिला	42	42%
कुल	100	100%
आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
18–30 वर्ष	28	28%
31–45 वर्ष	46	46%
46–60 वर्ष	20	20%
60+ वर्ष	6	6%

व्याख्या:

अधिकांश उत्तरदाता (46%) 31–45 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग है। महिलाओं की भागीदारी (42%) यह दर्शाती है कि मनरेगा में महिला सहभागिता उल्लेखनीय है।

2) रोजगार सृजन पर प्रभाव

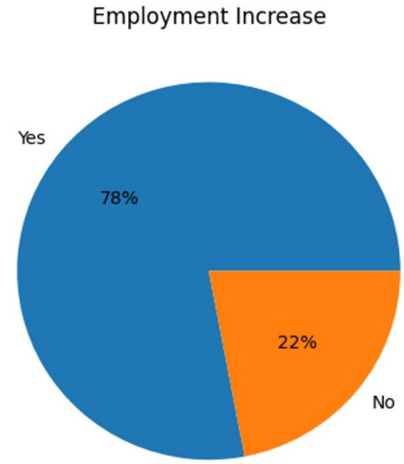

तालिका 2

तालिका 2 रोजगार अवसरों में वृद्धि		
उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	78	78%
नहीं	22	22%

व्याख्या:

78% उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिससे वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) सिद्ध होती है।

3) **आय स्तर में परिवर्तन**

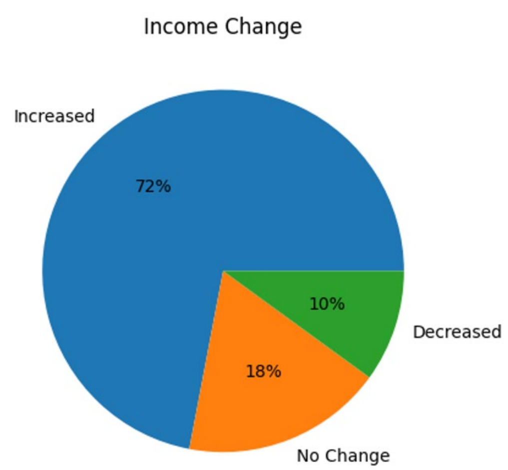

तालिका 3

तालिका 3 आय में बदलाव		
उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
वृद्धि हुई	72	72%
कोई परिवर्तन नहीं	18	18%

कमी हुई	10	10%

व्याख्या:

72% उत्तरदाताओं की आय में वृद्धि हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने आर्थिक स्थिति में सुधार किया है।

4) पलायन पर प्रभाव

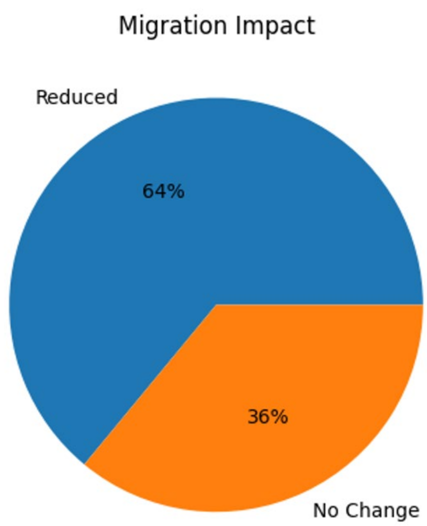

तालिका 4

तालिका 4 ग्रामीण पलायन में कमी		
उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
कमी आई	64	64%
कोई परिवर्तन नहीं	36	36%

व्याख्या:

64% उत्तरदाताओं ने बताया कि मनरेगा से पलायन में कमी आई है, जो स्थानीय रोजगार सृजन का संकेत है।

5) महिला सहभागिता

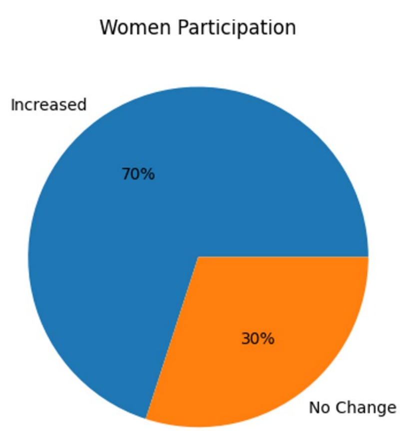

तालिका 5

तालिका 5 महिलाओं की भागीदारी		
उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
बढ़ी है	70	70%

कोई परिवर्तन नहीं	30	30%

व्याख्या:

70% उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है।

6) आधारभूत संरचना में सुधार

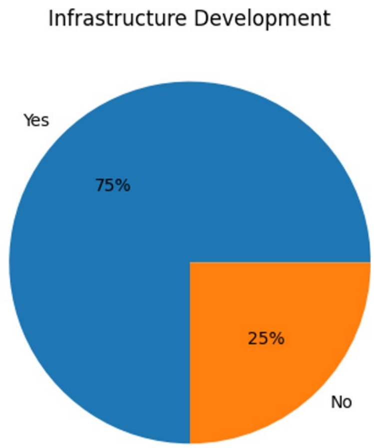

तालिका 6

तालिका 6 ग्रामीण विकास कार्य		
उत्तर	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
हाँ	75	75%
नहीं	25	25%

व्याख्या:

75% लोगों ने माना कि सड़क, तालाब, सिंचाई आदि में सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला है।

7) प्रमुख समस्याएँ

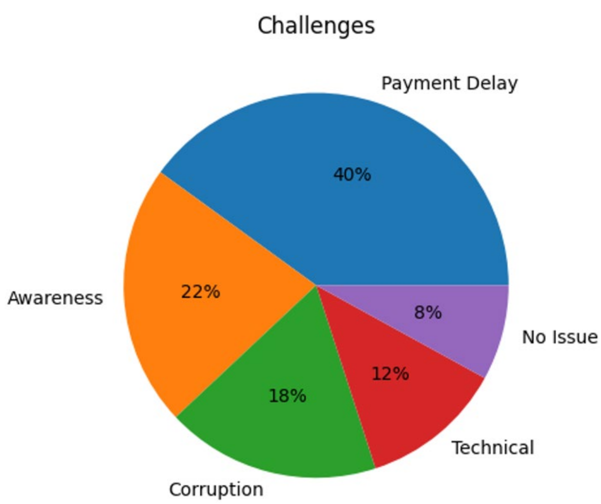

तालिका 7

तालिका 7 मनरेगा की चुनौतियाँ		
समस्या	आवृत्ति	प्रतिशत
मजदूरी भुगतान में देरी	40	40%
जागरूकता की कमी	22	22%
भ्रष्टाचार	18	18%
तकनीकी समस्याएँ	12	12%
कोई समस्या नहीं	8	8%

व्याख्या:

सबसे बड़ी समस्या मजदूरी भुगतान में देरी (40%) है, जो योजना के प्रभाव को प्रभावित करती है।

8) 100 दिनों का रोजगार

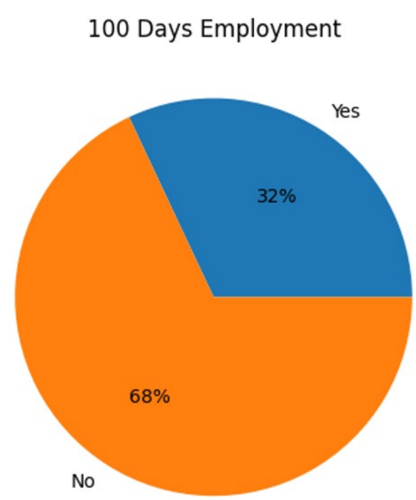

तालिका 8

तालिका 8 पूर्ण रोजगार की उपलब्धता		
उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	32	32%
नहीं	68	68%

व्याख्या:

केवल 32% लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला, जिससे कार्यान्वयन में कमी स्पष्ट होती है।

9) संतुष्टि स्तर

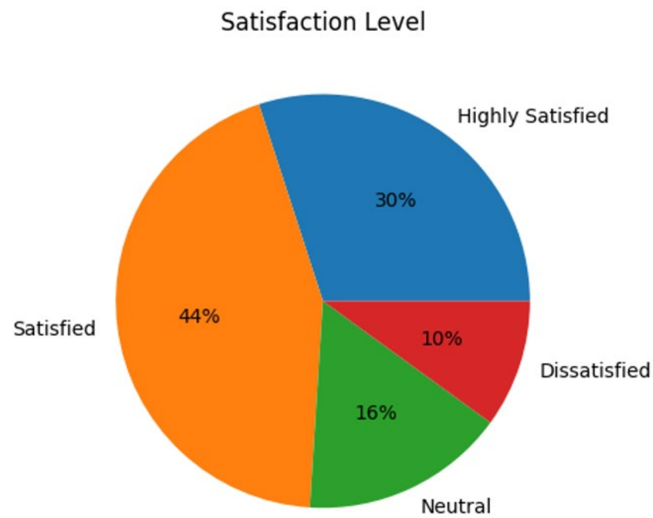

तालिका 9

तालिका 9 मनरेगा से संतुष्टि		
स्तर	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
अत्यधिक संतुष्ट	30	30%
संतुष्ट	44	44%
सामान्य	16	16%
असंतुष्ट	10	10%

व्याख्या:

74% उत्तरदाता संतुष्ट या अत्यधिक संतुष्ट हैं, जो योजना के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

6. परिणाम (FINDINGS)

अध्ययन के दौरान प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष सामने आए:

- ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि

मनरेगा के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से कृषि के ऑफ-सीजन में यह योजना ग्रामीण श्रमिकों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत बनकर उभरी है। इससे बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी (Underemployment) में कमी आई है।

- आय स्तर में सुधार

मनरेगा के माध्यम से प्राप्त मजदूरी ने ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि की है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। गरीब एवं वंचित वर्गों के लिए यह योजना आय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बनी है।

- ग्रामीण पलायन में कमी

स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण श्रमिकों का शहरों की ओर पलायन कुछ हद तक कम हुआ है। विशेषकर गरीब और भूमिहीन श्रमिकों को अपने ही गाँव में काम मिलने से सामाजिक स्थिरता में वृद्धि हुई है।

- महिला सशक्तिकरण में वृद्धि

मनरेगा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। महिलाओं को समान मजदूरी मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा परिवार एवं समाज में उनकी भूमिका अधिक सशक्त हुई है। यह योजना लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।

- मीण आधारभूत संरचना का विकास

इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, जल संरक्षण, तालाब, सिंचाई संरचनाएँ आदि कार्य किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है। इससे कृषि उत्पादकता और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- सामाजिक सुरक्षा और समावेशन

मनरेगा ने गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों तथा भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। यह योजना सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।

- मजदूरी भुगतान में देरी

अध्ययन में यह पाया गया कि मजदूरी भुगतान में अक्सर देरी होती है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या योजना की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।

- प्रशासनिक अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार

कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, और कार्यों में अनियमितता जैसी समस्याएँ पाई गई हैं, जिससे योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाता।

- जागरूकता की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में कई लाभार्थियों को योजना के प्रावधानों, अधिकारों और सुविधाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। इससे वे योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पाते।

- डिजिटल और तकनीकी चुनौतियाँ

डिजिटल भुगतान प्रणाली और ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली के कारण पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन तकनीकी जानकारी की कमी और इंटरनेट की सीमित उपलब्धता के कारण कुछ समस्याएँ भी सामने आई हैं।

- कार्य दिवसों की अपर्याप्तता

हालांकि योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश लाभार्थियों को पूरे 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाता है।

7. निष्कर्ष (CONCLUSION)

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मनरेगा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस योजना ने ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, गरीब एवं वंचित वर्गों की आय में वृद्धि करने तथा ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से कृषि के ऑफ-सीजन में यह योजना श्रमिकों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करती है, जिससे बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास—जैसे सड़क निर्माण, जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाएँ आदि—में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे कृषि उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। योजना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने उनके आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक स्थिति को मजबूत किया है, जो ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। मजदूरी भुगतान में देरी, प्रशासनिक अनियमितताएँ, भ्रष्टाचार, तकनीकी बाधाएँ तथा लाभार्थियों में जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ योजना की सफलता को सीमित करती हैं। इसके अलावा, सभी लाभार्थियों को 100 दिनों का रोजगार नहीं मिल पाना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मनरेगा बिहार में ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा का एक सशक्त उपकरण है, परंतु इसकी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

8. सुझाव (SUGGESTIONS)

मनरेगा योजना को अधिक प्रभावी एवं परिणामकारी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं:

- समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना

मजदूरी भुगतान में देरी को समाप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली (DBT) को अधिक प्रभावी और तेज बनाया जाए।

- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना

सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit) को नियमित एवं प्रभावी बनाया जाए ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण रखा जा सके।

- जागरूकता अभियान चलाना

ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रावधानों, अधिकारों और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाएँ।

- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना

लाभार्थियों और स्थानीय प्रशासन को डिजिटल प्रणाली (MIS, ऑनलाइन भुगतान) के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाए।

- 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना

प्रत्येक पात्र परिवार को वास्तव में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्यों की संख्या और विविधता बढ़ाई जाए।

- महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना

महिलाओं के लिए अनुकूल कार्यस्थल, बाल देखभाल सुविधाएँ तथा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

- स्थायी परिसंपत्तियों पर ध्यान देना

ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जो दीर्घकालिक लाभ दें, जैसे जल संरक्षण, कृषि सुधार, वृक्षारोपण आदि।

- स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाना

पंचायत स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो सके।

- शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत करना

लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक प्रभावी और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाए।

- निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार

योजना की प्रगति की नियमित निगरानी और स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए।।

REFERENCES

Ambasta, P., Shankar, P. S., & Shah, M. (2008). Two years of NREGA. Economic and Political Weekly, 43(8), 41–50.

Azam, M. (2012). Impact of job guarantee scheme. IZA Discussion Paper.

Banerjee, A., & Duflo, E. (2011). Making public works work. American Economic Journal, 3(1), 1–34.

Biswas, S. (2015). Impact of MGNREGA on Employment Generation and asset Creation in Rural India–A Critical Review. International Journal of Management and social science, 3(4), 350-357.

Biswas, S. (2015). Impact of MGNREGA on employment generation. International Journal of Management and Social Science.

Census of India. (2011). Population census report.

Chahal, M., & Kumar, P. (2020). Impact of MGNREGA on employment generation in Haryana. Journal of Economic policy and Research, 16(1), 56-63.

Chakraborty, S., Mishra, A. K., & Yan, H. (2025). Farming efficiency and MGNREGA.

Das, D. (2016). Role of MGNREGA in rural employment: a study of Barpeta district of Assam, India. International Journal of Humanities & Social Science Studies, 2(6), 241-248.

Das, S. (2019). Economic sustainability under MGNREGA. Research Review Journal.

Deininger, K., & Nagarajan, H. (2011). MGNREGA evolution and impacts. World Bank.

Dey, D. K. (2016). Employment generation and asset building. Journal of Rural Development.

Dreze, J., & Khera, R. (2010). The battle for employment guarantee. Economic and Political Weekly, 45(18), 43–51.

Dreze, J., & Khera, R. (2011). The battle for employment guarantee. Oxford University Press.

Dreze, J., & Sen, A. (2013). An uncertain glory: India and its contradictions. Princeton University Press.

Dutta, P., Murgai, R., Ravallion, M., & Van de Walle, D. (2012). Does India's employment guarantee scheme guarantee employment? Economic and Political Weekly, 47(16), 55–64.

Esteves, T., et al. (2013). Livelihood vulnerability reduction. Economic and Political Weekly.

Government of Bihar. (2023). Economic Survey of Bihar.

Government of India. (2005). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Ministry of Rural Development.

Hirway, I., Saluja, M. R., & Yadav, B. (2010). Employment guarantee and pro-poor growth. Academic Foundation.

ILO. (2020). World employment report.
Khera, R. (2011). NREGA wages. Economic and Political Weekly.
M. S. (2007). MGNREGA and agricultural employment. Economic and Political Weekly, 42(52), 42–49.
Ministry of Rural Development. (2022). MGNREGA annual report.
Mishra, M. K. (2024). An impact assessment study of MGNREGA in Bihar.
NABARD. (2021). Rural development report.
NSSO. (2021). Employment and unemployment survey.
Nagaraj, N., Bantilan, C., Pandey, L., & Roy, N. S. (2016). Impact of MGNREGA on rural agricultural wages, farm productivity and net returns: an economic analysis across SAT villages. Indian Journal of Agricultural Economics, 71(02), 176-190.
Pandey, A. K. (2023). Performance of mgnrega in Chhattisgarh-An analysis. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 13(7), 23-30.
Planning Commission. (2019). Rural development report. Government of India.
Raju, G., & Sharma, N. K. (2025). Performance of MGNREGA in Andhra Pradesh Post Bifurcation: A Study of the Marginalized Population-Segments in the Rural Areas. South Asian Journal of Management, 11(1).
Shah, P. (2024). Factors Affecting the Adoption of MGNREGA Work in India: Empirical Evidence from Indian States. INTERNATIONAL JOURNAL, 9(10), 4329-4339.
UNDP. (2021). Rural livelihood report.
World Bank. (2020). Social protection and jobs report.